जल्द आएगी एसएएफ नीति : मनोज

इन्वेस्ट यूपी के गोल मेज सम्मेलन में कई कंपनियों ने दिखाई रुचि

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ : मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) नीति जल्द लाई जाएगी। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। अभी तक किसी भी राज्य की एसएएफ नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।

ताज होटल में रविवार को इन्वेस्ट यूपी की तरफ से आयोजित गोल मेज सम्मेलन में उन्होंने एसएएफ नीति के तहत प्रोत्साहनों, सुविधाओं और कई संबंधित बिंदुओं को रेखांकित किया। कहा कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध कृषि संपदा, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और औद्योगिक नीतियां प्रदेश को एसएएफ का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के अमल में आने और एसएएफ उद्योगों की स्थापना के बाद किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। एसएएफ़ उद्योग की बायोमास और अनाज-आधारित गन्ने की खोई, धान की भूसी व गेहूं का भूसा की मांग किसानों के लिए नए बाजार का अवसर पैदा करेगी। स्थानीय कृषि

रविवार को आयोजित गोल मेज सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ● सूचना विभाग

उत्तर प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपये का होगा निवेश

क्षेत्रों से सीधे कच्चा माल खरीदने से, यह क्षेत्र ग्रामीण आय को बढ़ाने और बेहतर मूल्य दिलाने में मददगार होगा। सम्मेलन में ग्रीनको, एएम ग्रीन्स, ई-20 ग्रीनफ्यूल्स, न्यू एरा क्लीन टेक और मालब्रोस ग्रुप सहित 18 से अधिक कंपनियों ने राज्य में एसएएफ इकाइयां स्थापित करने में रुचि व्यक्त की। इन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने में रुचि दिखाई है।

यह और उप्र की राजनीति, सरकार और अपराध संबंधित अन्य खबरें www.jagran.com पर पढ़ें

लंबित जीएसटी मामलों के समाधान से बढ़ेगा निवेशकों का भरोसा : सीएस

मुख्य सचिव (सीएस) मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि उद्योगों के लंबित जीएसटी के मामलों के समाधान से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों को निवेश के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन सुविधाएं और जीएसटी प्रतिपूर्ति में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीएसटी प्रतिपूर्ति मामलों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से निपटाना होगा। ताज होटल में इन्वेस्ट यूपी की तरफ से आयोजित संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है। हमारा लक्ष्य निवेशकों के लिए एक सहज और सुविधाजनक वातावरण बनाना है। संवाद सत्र में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने जीएसटी से संबंधित तकनीकी और कानूनी चुनौतियों पर चर्चा की। मुद्दा उठाया कि निवेश की परियोजनाओं को लेकर प्रोत्साहन राशि मिलने में देरी होती है। संवाद सत्र में वरुण बेवरेजेज, बलरामपुर चीनी मिल्स और पसवाड़ा पेपर्स लिमिटेड सहित कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।